ब्रिक्स से 417 अरब डॉलर का कारोबार

चीन अकेले से 112 अरब डॉलर का व्यापार घाटा

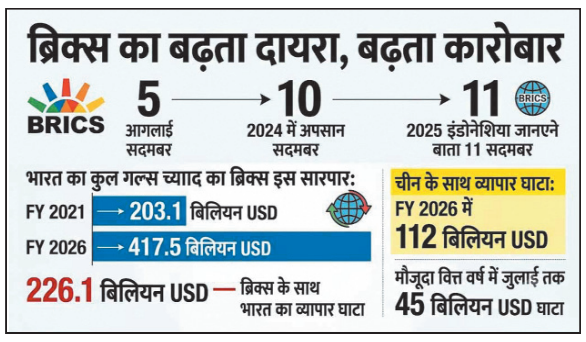

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली , 11 सितम्बर . भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन समेत सदस्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने पर जोर रहेगा. खासतौर पर भारत के बड़े व्यापार घाटे को कम करने, भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और स्थानीय मुद्राओं में आपसी कारोबार को बढ़ावा देने पर चर्चा हो सकती है.

उद्योग जगत को उम्मीद है कि चीन की ओर से दुर्लभ खनिज, इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत उपकरणों के निर्यात पर लगाई गई पाबंदियों तथा कारोबारियों को बिजनेस वीजा मिलने में हो रही देरी का मुद्दा भी उठेगा.चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पिछले वित्त वर्ष में 112 अरब डॉलर रहा. चालू वित्त वर्ष में भी जुलाई तक यह करीब 45 अरब डॉलर पहुंच चुका है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार, ब्रिक्स देशों के साथ भारत का वस्तु व्यापार वित्त वर्ष 2021 के 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 417.5 अरब डॉलर हो गया. हालांकि इसी अवधि में ब्रिक्स देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा तीन गुना बढ़कर 226.1 अरब डॉलर हो गया, जो समूह में सबसे अधिक है. चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा पिछले वित्त वर्ष में 112 बिलियन डॉलर था. वर्तमान वित्त वर्ष में भी जुलाई तक यह लगभग 45 बिलियन डॉलर हो चुका है. ब्रिक्स देशों से भारत का गुड्स ट्रेड वित्त वर्ष 2021 के 203.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 417.5 बिलियन डॉलर हो गया.

कारोबार के लिए भरोसेमंद माहौल जरूरी : जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को ब्रिक्स बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में कारोबार के लिए ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है, जो स्थिर, पारदर्शी और भरोसेमंद हो. उन्होंने कहा कि दुनिया इस समय बड़े राजनीतिक और आर्थिक बदलावों के दौर से गुजर रही है और अस्थिरता, अनिश्चितता तथा जटिलता वैश्विक व्यवस्था की पहचान बन गई है. ऐसे में ब्रिक्स देशों को आर्थिक झटकों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े और प्रतिस्पर्धी बने रहने पर ध्यान देना होगा. जयशंकर ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने का अर्थ आत्मनिर्भरता बढ़ाना है. इसके लिए कारोबारी व्यवहार बाजार के वास्तविक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए.

इक्विटी फंड्स में आया 29,329 करोड़ का निवेश

- जुलाई के मुकाबले निवेश में करीब 19% की बढ़ोतरी
- इक्विटी एसआईपी ने भी बनाया नया रिकॉर्ड

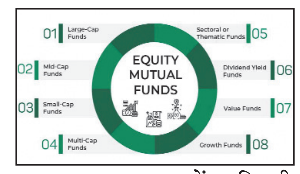

नवभारत न्यूज नेटवर्क.
नई दिल्ली , 11 सितंबर. जुलाई में गिरावट के बाद अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी. अगस्त में इक्विटी ओरिएंटेड योजनाओं में 29,328.62 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश आया, जो जुलाई के 24,097.39 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 19 फीसदी अधिक है. इससे पहले जून में इन योजनाओं में 28,973 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था.

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में इक्विटी योजनाओं के साथ नियमित निवेश का रुझान भी मजबूत रहा. इक्विटी एसआईपी के जरिए अगस्त में 32,297 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जबकि जुलाई में यह 31,961 करोड़ रुपए था. यानी एक महीने में एसआईपी योगदान करीब 336 करोड़ रुपए बढ़ा.

श्रेणीवार देखें तो अगस्त में स्मॉलकैप फंड निवेशकों की पहली पसंद रहे. इनमें 7,973.33 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश आया. इसके बाद मिडकैप फंड में 6,989.40 करोड़ और फ्लेक्सीकैप फंड में 7,767.50 करोड़ रुपए का निवेश हुआ. स्मॉलकैप और मिडकैप को मिलाकर 14,962.73 करोड़ रुपए आए.

इस तरह रहा इक्विटी फंड्स में कैटेगरीवार निवेश

फंड कैटेगरी	अगस्त में निवेश इनफ्लो/आउटफ्लो	जुलाई	बदलाव
स्मॉल-कैप	7,973.33 करोड़	7,767.50 करोड़	205.83 करोड़ ज्यादा
मिड-कैप	6,989.40 करोड़	6,192.31 करोड़	797.09 करोड़ ज्यादा
स्मॉल + मिड-कैप	14,962.73 करोड़	13,959.81 करोड़	1,002.92 करोड़ ज्यादा
फ्लेक्सी-कैप	5,059.42 करोड़	—	—
मल्टी-कैप	3,732.77 करोड़	—	—
लार्ज-कैप	-1,147.36 करोड़	-1,321.69 करोड़	174.33 करोड़ कम
ईएलएसएस	-1,078.32 करोड़	—	नेट निकासी
सेक्टोरल फंड्स	-53.19 करोड़	—	नेट निकासी

कोयले की किल्लत से बिजलीघरों की सांसें अटकीं

- 23.41 लाख टन होना चाहिए था भंडार, मिला सिर्फ 8 लाख टन
- रोज 78 हजार टन खपत, 1.03 लाख टन हो रही आपूर्ति

नवभारत न्यूज नेटवर्क
लखनऊ, 11 सितम्बर बारिश ने कोयला खदानों से उत्पादन और बिजलीघरों तक उसके प्रेषण की रफ्तार धीमी कर दी है. इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के तापीय बिजलीघरों पर पड़ा है.

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के छह तापीय बिजलीघरों में कोयले का भंडार घटकर निर्धारित मानक के महज 34 प्रतिशत तक रह गया है. 9,115 मेगावाट की कुल क्षमता वाले अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, जवाहरपुर, पनकी और परीछा बिजलीघरों में सामान्य स्थिति में 18 दिनों की जरूरत के लिए करीब 23.41 लाख टन कोयला होना चाहिए, लेकिन अभी करीब आठ लाख टन ही उपलब्ध है. यानी मानक से करीब 15.41 लाख टन कम भंडार है. सीमित कोयले के कारण कुछ इकाइयों को उनकी क्षमता से कम भार पर चलाना पड़ रहा है. हालांकि फिलहाल रोज करीब 78 हजार टन कोयले की खपत के मुकाबले 1.03 लाख टन की आपूर्ति हो रही है, जिससे भंडार में धीरे-धीरे सुधार की उम्मीद है. दूसरी ओर, बारिश लंबी खिंचने पर खदानों में उत्पादन और परिवहन प्रभावित होने से आपूर्ति घटने का खतरा बना हुआ है. इसका असर बिजली उत्पादन पर भी दिखाई दे रहा है.

मत्स्य योजना से बढ़ी मछली उत्पादकता

- उत्पादकता 2.3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3.3 टन
- मछुआरों को बीमा और आजीविका सहायता

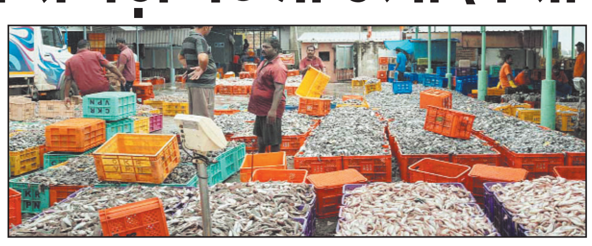

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 11 सितंबर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. यह मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित और सतत विकास योजना है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 05 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और विपणन तक मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाना और मजबूत करना, पता लगाने की क्षमता को बढ़ाना और एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करना है, साथ ही साथ मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करना है.भारत में मछली की उत्पादकता वित्त वर्ष 2015 के 2.3 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में 3.3 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है. यह वृद्धि सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना और 'नीली क्रांति' जैसी पहलों के कारण संभव हुई है, जिससे कुल मछली उत्पादन में भी भारी उछाल आया है. इस योजना के कार्यान्वयन से सरकार का लक्ष्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को 20-25% से घटाकर 10% करना, मछुआरों और मछली पालकों की आय को दोगुना करना और 55 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना है.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रमुख लक्ष्य

- वित्त वर्ष 2019 में मछली उत्पादन 13.75 मिलियन मीट्रिक टन था, जिसे वित्त वर्ष 2025 तक बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना है.
- मत्स्यपालन की उत्पादकता को तीन टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर करना.
- घरेलू स्तर पर मछली की खपत को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम से बढ़ाकर 12 किलोग्राम करना.
- कृषि के सकल मूल्यवर्धन में मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान वित्त वर्ष 2019 में 7.28% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 तक लगभग 9% हो जाएगा.
- वित्त वर्ष 2019 में निर्यात राजस्व 46,589 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 तक 1,00,000 करोड़ रुपये तक दोगुना करने का लक्ष्य.

444 दिन की एफडी में 3 लाख पर मिलेगा 24 हजार ब्याज

- 3 लाख की जमा पर करीब 3.24 लाख की परिपक्वता राशि
- 60 साल से अधिक उम्र वालों को सामान्य से ज्यादा ब्याज

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 11 सितंबर अगर आप शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से बचते हुए अपनी रकम पर तय रिटर्न चाहते हैं, तो सावधि जमा आपके लिए एक विकल्प हो सकती है. बैंक ऑफ बड़ौदा की 444 दिन की सावधि जमा योजना में सामान्य ग्राहकों को 6.45 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जा रहा है.

वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर अधिक है. ऐसे में एकमुश्त रकम को कुछ समय के लिए सुरक्षित जगह पर रखने वाले निवेशकों के लिए यह योजना आकर्षक हो सकती है.

मान लीजिए कोई सामान्य ग्राहक 444 दिनों के लिए 3 लाख रुपये जमा करता है. बैंक की बताई गई 6.45 प्रतिशत ब्याज दर के आधार पर इस अवधि में ब्याज करीब 24 हजार से 24,300 रुपये के आसपास हो सकता है. यानी मूल जमा राशि में ब्याज जोड़ने के बाद परिपक्वता पर करीब 3.24 लाख रुपये मिल सकते हैं.

एनएसई आईपीओ का रास्ता हुआ साफ

- 17 सितंबर से खुलेगा 22,569 करोड़ का इश्यू
- करीब दशक बाद सूचीबद्ध होने की तैयारी

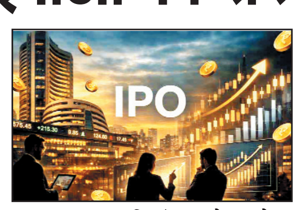

नवभारत न्यूज नेटवर्क
मुंबई,11 सितंबर देश के सबसे बड़े शेयर बाजार मंच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम का रास्ता अब साफ हो गया है. एनएसई ने अपने आईपीओ के लिए 1,700 से 1,785 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है.

करीब 22,569 करोड़ रुपए का यह इश्यू 17 सितंबर को खुलेगा और 21 सितंबर तक निवेशकों के लिए उपलब्ध रहेगा. एंकर निवेशकों के लिए बोली 16 सितंबर से शुरू होगी, जबकि शेयरों की सूचीबद्धता 24 सितंबर को प्रस्तावित है.

ऊपरी मूल्य दायरे पर इश्यू का आकार 22,569 करोड़ रुपए और निचले स्तर पर करीब 21,494 करोड़ रुपए रहेगा. इस आकार के साथ एनएसई का आईपीओ देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम बन जाएगा.

एनएसई का पूरा आईपीओ बिक्री पेशकश यानी मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी बेचने के रूप में आएगा. इसमें करीब 12.64 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे. इसका मतलब है कि आईपीओ से मिलने वाली रकम सीधे एनएसई को नहीं मिलेगी, बल्कि हिस्सेदारी बेचने वाले मौजूदा शेयरधारकों को जाएगी.

आईएमएफ ने भारत के आंकड़ों को सराहा

नवभारत न्यूज नेटवर्क.
वॉशिंगटन ,11 सितंबर भारत की आर्थिक आंकड़ा प्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने देश के सांख्यिकीय ढांचे को आधुनिक बनाने की कोशिशों का स्वागत किया है.

आईएमएफ ने कहा कि भारत द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला को शामिल करने से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान और अधिक सटीक बनाने में मदद मिलेगी. आईएमएफ के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि भारत को आंकड़ों की गुणवत्ता और सांख्यिकीय ढांचे को और मजबूत करने के प्रयास जारी रखने चाहिए. उन्होंने बताया कि भारत की वास्तविक जीडीपी दूसरी तिमाही में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो आईएमएफ के कर्मचारियों के अनुमान और अन्य विशेषज्ञों के औसत अनुमान से भी बेहतर रही.

वेकोलि सीएमडी डॉ. पांडे को 'एमिनेंट इंजीनियर अवॉर्ड'

मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर में किया सम्मानित

नवभारत कनेक्ट
नागपुर, 11 सितम्बर. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खनन अभियंता सम्मेलन में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) के सीएमडी डॉ. हेमंत शरद पांडे को 'एमिनेंट इंजीनियर अवॉर्ड' से सम्मानित किया।

खनन इंजीनियरिंग और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया।सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने विदर्भ की खनिज संपदा और गढ़चिरौली के लौह अयस्क भंडारों का उल्लेख करते हुए क्षेत्र में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 50 एमटीपीए इस्पात उत्पादन क्षमता विकसित किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश की शुरुआती आठ कोयला गैसीकरण परियोजनाओं में से चार विदर्भ को मिली हैं। डॉ. पांडे ने कहा कि नागपुर को देश की खनन राजधानी के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वेकोलि की 12 खदानों में 18 महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की पहचान की गई है।

समाचार विशेष

कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतार सकी

हमीरपुर, 11 सितंबर. पंचायत समिति बमसन टौणी देवी (बीडीसी) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव ने क्षेत्र की स्थानीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है.

इस चुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी तक मैदान में नहीं उतार पाई, जबकि भाजपा से जुड़े दो-दो प्रत्याशियों के बीच अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मुकाबला हुआ. बमसन में इस बार सियासी तस्वीर कुछ ऐसी रही कि मुकाबला कांग्रेस बनाम बीजेपी के बजाय भाजपा बनाम भाजपा बन गया. एसडीएम हमीरपुर संजीत सिंह की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे चुनावी बैठक शुरू हुई. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति नहीं बनने के बाद मतदान करवाया गया. अध्यक्ष पद के लिए जंदड़ू वार्ड से पूजा कुमारी और पौहंज वार्ड से सुषमा देवी आमने-सामने थीं. मतदान में पूजा कुमारी को 10 मत मिले, जबकि सुषमा देवी के पक्ष में 5 मत पड़े. इस तरह पूजा कुमारी ने पांच मतों के अंतर से जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद हासिल किया. उपाध्यक्ष पद पर भी मुकाबला भाजपा से जुड़े दो प्रत्याशियों के बीच रहा.

पटनौण वार्ड के सुरेंद्र सिंह और बगवाड़ा वार्ड के विपिन कुमार के बीच हुए चुनाव में सुरेंद्र सिंह को 10 मत, जबकि विपिन कुमार को 5 मत प्राप्त हुए.

चुनाव ने कई सवाल छोड़े

एक तरफ कांग्रेस चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी नहीं उतार सकी, तो दूसरी तरफ भाजपा के ही प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला हुआ. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस ने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा? क्या पार्टी के पास पर्याप्त समर्थन नहीं था या संगठन स्तर पर रणनीतिक चूक हुई? वहीं भाजपा के भीतर हुए इस मुकाबले को क्या सामान्य लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा माना जाए या इसके पीछे स्थानीय स्तर की राजनीतिक खींचतान भी थी? फिलहाल बमसन (बीडीसी) चुनाव ने क्षेत्र की राजनीति में कई सवाल छोड़ दिए हैं.

पूर्व मेयर विशाखा राउत की पार्षदी खत्म

कुनबी जाति प्रमाण आमान्य, उद्धव को करारा झटका

मुंबई, 11 सितंबर. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव हुए अभी साल भी पूरा नहीं हुआ है और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को करारा झटका लगा है.

मुंबई की मेयर रह चुकीं विशाखा राउत की सदस्यता को बीएमसी ने रद्द कर दिया है. वह दादर के वार्ड नंबर 191 से चुनी गई थीं. यह सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी. विशाखा राउत ने जो जाति प्रमाण पत्र जमा किया था. उसे अवैध घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है. बीएमसी ने विशाखा राउत के छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है. पालघर में बने उनके ओबीसी सर्टिफिकेट को आमान्य घोषित किया गया था.

विशाखा राउत ने दादर के वार्ड नंबर 191 से बीएमसी का चुनाव लड़ा था, जो कि ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित सीट थी. चुनाव जीतने के बाद राउत के प्रतिद्वंद्वी शिंदे गुट के सदा सरवणकर की बेटी प्रिया सरवणकर ने शिकायत दर्ज कराई थी. पालघर जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति ने पाया कि उनका कुनबी (ओबीसी) प्रमाण पत्र गलत क्षेत्राधिकार से जारी किया गया था, जिसके कारण समिति ने उसे अमान्य घोषित कर दिया. मुंबई नगर निगम अधिनियम के नियमों के तहत यदि किसी निर्वाचित पार्षद का जाति प्रमाण पत्र अमान्य हो जाता है, तो उसकी सदस्यता स्वत: समाप्त हो जाती है. इसके आधार पर महाराष्ट्र के नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर उन्हें 20 अगस्त 2026 से पार्षद पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया और 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया.

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

विशाखा राउत ने बीएमसी और जाति पड़ताल समिति की इस कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया. शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं (जैसे संजय राउत) और खुद विशाखा राउत ने इसे सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक प्रतिशोध वाली कार्रवाई बताया है.

प्रभार से मनोज सिन्हा की भूमिका पर उठे सवाल

जम्मू, 11 सितंबर. जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा छुट्टी पर हैं. वे अमेरिका गए हैं, जहां उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू की आईआईटी के पुराने छात्रों के एक कार्यक्रम को संबोधित करना है.

उनके और भी कार्यक्रम हैं. उनके छुट्टी पर जाने के बाद लद्दाख के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. ध्यान रहे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी छुट्टी पर गईं लेकिन उनका प्रभार किसी को नहीं दिया गया. हालांकि वहां भी बदलाव की चर्चा है. बहरहाल, सवाल है कि मनोज सिन्हा लौट कर फिर जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे या उनको कोई और भूमिका मिलने वाली है?

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला और उससे पहले भाजपा सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने में लगी है. ऊपर से मनोज सिन्हा को बतौर उप राज्यपाल काम करते हुए छह साल हो गए है.

विशेष जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद से संवैधानिक राजनीति तक दो गुट आमने-सामने

जमात-ए-इस्लामी की अंदरूनी जंग

श्रीनगर, 11 सितंबर. जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी की अंदरूनी लड़ाई अब बंद कमरों की बहस से निकलकर खुले राजनीतिक संघर्ष में पहुंच गई है. एक ओर जमात से अलग हुआ धड़ा जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट (जेडीएफ) के नाम से चुनावी और संवैधानिक राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जमात का मूल नेतृत्व उसकी वैचारिक पहचान से समझौता करने के सवाल पर इस नए राजनीतिक प्रयोग को कठघरे में खड़ा कर रहा है. दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दायरा अब विचारधारा से बढ़कर संगठन की विरासत, संस्थानों और संपत्तियों तक पहुंच गया है.

श्रीनगर में गुलाम कादिर वानी और अहमदुल्लाह पर्रे मलिक समेत अलग हुए धड़े के नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें समर्थकों के बीच बदनाम करने के लिए 'गद्दार' और 'बिकाऊ' जैसे तमगों का इस्तेमाल किया जा रहा है. पर्रे ने केंद्र के साथ संवाद का स्वागत करते हुए युवाओं से संविधान के दायरे में अपने मुद्दे उठाने की अपील की. यही बयान इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत है, क्योंकि कश्मीर की राजनीति में जमात-ए-इस्लामी की पहचान केवल एक धार्मिक-सामाजिक संगठन की नहीं रही है. दशकों तक यह संगठन अलगाववादी राजनीति के प्रभावशाली नेटवर्क का हिस्सा रहा और आतंकवाद के दौर में इसके कैडर तथा उससे जुड़े सामाजिक नेटवर्क की भूमिका पर सुरक्षा एजेंसियां गंभीर सवाल उठाती रही हैं. ऐसे में उसी पृष्ठभूमि से निकला एक धड़ा यदि अब चुनाव और संविधान को राजनीतिक रास्ता बता रहा है तो इसे महज संगठनात्मक टूट नहीं, बल्कि एक बड़े वैचारिक बदलाव के संकेत के रूप में देखा जाएगा.

सवाल जमात की विचारधारा का -जमात के पूर्व प्रमुख गुलाम मोहम्मद भट्ट ने जेडीएफ की चुनावी राजनीति पर ही सवाल उठा दिया है. उनका तर्क है कि यदि जेडीएफ अपने राजनीतिक घोषणापत्र में समाजवाद जैसी अवधारणाओं को स्थान देता है तो फिर उसे इस्लामी विचारधारा की राजनीतिक निरंतरता के रूप में पेश करना विरोधाभासी है. भट्ट का कहना है कि जमात का किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है. संगठन ने प्रतिबंध स्वीकार किया है और प्रतिबंध के खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाएगा.

फलाह-ए-आम ट्रस्ट पर टकराव ने बढ़ाई तल्खी

विचारधारा की लड़ाई अब संपत्ति विवाद से भी जुड़ गई है. फलाह-ए-आम ट्रस्ट की संपत्तियां इस संघर्ष का केंद्र बनती जा रही हैं. गुलाम मोहम्मद भट्ट ने आरोप लगाया है कि जमात से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जे की कोशिश हो रही है और जेडीएफ इन परिसरों का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए कर रहा है. उनके अनुसार इसमें सरकार का सहयोग भी प्राप्त है. जवाब में अहमदुल्लाह पर्रे ने जबरन कब्जे के आरोप को खारिज करते हुए दावा किया कि 2024 में ट्रस्ट की संपत्ति के एक हिस्से के इस्तेमाल के लिए बाकायदा टेनेंसी एग्रीमेंट किया गया था.